

**[श्री शान्ति त्यागी]**

की पिराई शुरू हो जायेगी। गन्ने का उत्पादन लागत बढ़ गया है। मान्यवर, आप भी ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ गन्ना बड़ी मात्रा में पैदा होता है। मान्यवर, खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। मैं एक मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब गन्ना खेत में बड़ा हो जाता है तो उसको बांधा जाता है। बहुत से भाई नहीं जानते हैं कि वह गिरे नहीं इसलिए उनके पेड़ों को मिलाकर बांधते हैं। तो एक कच्चा बीघा के गन्ने को बांधने के लिये अगर किसी मजदूर को रखें तो वह 30 रुपये गन्ना बांधने का चार्ज करता है। जब कि कुछ दिन पहले यह मजदूरी सिर्फ 5 रुपये थी। इसमें 25 रुपये का इजाफा हो गया है। इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि किसानों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गन्ना पैदा करने वाले किसानों को कम से कम 32 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत की घोषणा इस सदन में करें।

अंत में मैं गन्ने की दरों में तबदीली के साथ साथ सरकार से यह भी आग्रह करूँगा कि चीनी मिलों को लगाने के संबंध में केंद्रीय सरकार की जो नीति है वह बहुत सख्त है। उसको थोड़ा उदार करें और जहाँ चीनी मिल खोलने की जरूरत है, जहाँ पर इसके लिये किसानों की मांग है और जहाँ गन्ना उपलब्ध है वहाँ चीनी मिलों को खोलने के लिये सरकार लाइसेंस दे। यह मांग भी मेरी आपके माध्यम से सरकार से है।

अंत में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कम से कम 32 रुपये गन्ने का मूल्य निश्चित किया जाए और चीनी मिलों के

खोलने के बारे में उदार नीति सरकार बनाये यह मेरा आग्रह है। मैं आशा करता हूँ, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि इस वक्त जो माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, इस सदन में बैठे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब किसान हैं और कोई भी गैर किसान मंत्री यहाँ पर नहीं है। इसलिये वे एक राय से इस सदन के माध्यम से यह मांग करें कि गन्ने का मूल्य कम से कम 32 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और चीनी मिलों को खोलने के बारे में सरकार अपनी नीति को उदार बनाये।

**श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :**  
(महाराष्ट्र) : मैं शान्ति त्यागी का समर्थन करता हूँ।

**श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश)**  
मैं मांग करता हूँ कि

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESHDESAI): After this, there are two more special mentions, and after that is over, Shri Bhajan Lai will make a statement.

**श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) :**  
इसका हम समर्थन करना चाहेंगे। यह गन्ने का मुसला है और इस संबंध में त्यागी जी ने जो कहा है हम उससे विलुल सहमत हैं ताकि किसानों का एक्सप्लोइटेशन न हो। हम सब इसका समर्थन करते हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) :** हो गया है पूरे सदन का समर्थन।

Need for Financial Assistance to Gujarat

**श्री छोटूभाई मुखाभाई पटेल (गुजरात) :**  
उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से गुजरात के आर्थिक जीवन का जो महत्वपूर्ण मसला है वह उठा रहा हूँ। गुजरात का समुद्र का किनारा करीबन 16 सौ किलोमीटर है और सारे किनारे पर, गुजरात के कोस्टल एरिया में बस्तियाँ बसी हुई हैं। महोदय, इसके कारण सलाइन वाटर कल्टीवेशन की लैंड को खराब कर रहा है। जिससे हमारे गुजरात की करीबन 10 हजार एकड़ जमीन सलाइन वाटर से खराब हो गई है। कई गांवों में इसका बहुत बुरा असर हुआ है। इसके कारण कई गांवों को खाली करवाया है। गुजरात सरकार ने उसके लिये रेक्लेमेशन बोर्ड भी बनवाया है और सिविल/ज कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। फिर भी गुजरात के लिये यह प्रावलम बहुत बड़ी है। वहाँ पर जो सलाइन वाटर की प्रावलम है गुजरात सरकार अपने आप इससे नहीं निपट सकती। इसलिये मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करना हूँ कि गुजरात की सरकार को इस प्रावलम से निपटने के लिये ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए। हमारे यहाँ कई परियोजनाएँ हैं।

नर्मदा की जो पाइपलाइन परियोजना एन०आर०आई० की है जो प्लानिंग कमिशन को प्रस्तुत की गई है उसको जल्दी से जल्दी मंजूर कराया जाए और इस नर्मदा परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फ्रैण प्रोग्राम बनाया जाए वरन् सौराष्ट्र के सुरेन्द्र नगर, जूनागढ़ तथा जामनगर के जिलों की जमीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है इस परियोजना के पूरा होने के इन जिलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकेगा। इसके इलावा हमारे यहाँ की 29 मध्यम कक्षा की परियोजनाएँ हैं, 6 मोटी परियोजनाएँ 2463 RSS/88—24

हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए तो मुझ को यह लगता है कि इससे हम बड़े बड़े रिजर्वॉयर 250 लम्बाई, 150 चौड़ाई तथा 10 मीटर गहराई के बना सकेंगे। यह रिजर्वॉयर समुद्र के किनारे बनाए जाएंगे जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे यहाँ सलाइन वाटर बहुत ज्यादा बन रहा है इससे हम उसके बारे में कुछ कर सकेंगे। टेक्नोलोजी मिशन जो अभी काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत बड़ा काम है इसलिए टेक्नोलोजी मिशन को वहाँ ज्यादा काम करना चाहिये। मैं आपको एक एग्जम्पल दे रहा हूँ डांग जिले में 100 से 100 इंच पानी बरसता है लेकिन डांग और धरमपुर के एरिया में गर्मियों में टैंकरो के द्वारा पानी भोजना पड़ता है। यह सिचुएशन वहाँ पर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिक्लेमेशन के बारे में तथा पोर्टेबल ड्रिपिंग वाटर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिये। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फ्लोराइड-युक्त वाटर है और गिनी-बोम वाटर बहुत ज्यादा है। मैं यह कह रहा हूँ कि 6 स्टेड्स में यह गिनी-बोम वाटर है, 13 स्टेड्स में फ्लोराइड वाटर है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में ढाई करोड़ लोग फ्लोराइड वाटर की समस्या से पीड़ित हैं और 14 स्टेड्स में आइरन वाटर है और 14 स्टेड्स में सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर से 14 स्टेड्स प्रभावित है जो कोस्टल एरिया की स्टेड्स हैं। मेरी आपसे विनती है कि सलाइन वाटर की समस्या के कारण हमारे यहाँ की जमीन

□ [श्री छोटे भाई सुखा भाई पटेल]

बहुत बिगड़ गई है, वहाँ का पानी स्वाइन हो गया है इसलिए इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मदद करे और इसके लिए मेरी यह मांग है कि कोस्टल एरिया सब-प्लान बनाई जाए ताकि यह समस्या हल हो सके और इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रेष प्रोग्राम बनाए जाएं तो यह गुजरात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI RAOOF VALIULLAH (GUJARAT) : Mr. VicerChairman, Sir, this problem of salinity has been raised again and again in this House over the last five years, but no concrete steps have been taken either by the State Government or by the Central Government. Fortunately, with the starting of the technology mission, for the first time, the problem of salinity and brackishness is being tackled on a war footing. Rs. 5 crores have been earmarked. As my hon. colleague pointed out, the problem of salinity in the entire coastal area of Gujarat should be tackled on a very urgent basis. I would, therefore, request the Government, particularly, the hon. Minister of Rural Development, to look into this."

#### **Stoppage of Steamer Service by S.C.I in Goa**

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, through you. I would like to draw the attention of the Government to the plight of the people residing there.

Konkan coast due to the stoppage of steamer service by the S.C.I.

Since the liberation of Goa and even before that, as you must be well aware, Goa was linked with Bombay and other coastal districts of Maharashtra with steamer service catering to the needs of the people on the Konkan coast. The steamer service did not only help passenger service but also was useful for the transport of perishable farm and other livestock products to the cities of Bombay and Panjim. It was the most convenient and cheap mode of transport for the old and the sick who wanted to avail of medical treatment in the cities. But to the utter surprise of the people of the Konkan coast, the steamer service was withdrawn on the plea that there was need to put the steamer service to better use elsewhere for a greater national cause. As such, the people of the area did not object to it. Now, it appears from the Government's utterances that the steamer service may not be continued under the pretext that it is running at a loss.

Sir, the main purpose of any public sector transport undertaking is not of commercial nature, to make profit, but to cater to the needs of the traveling public. It should be service-oriented. It is hoped that the Central Government will cooperate with the Governments of Maharashtra and Goa to resume this service during this season at least to alleviate the problems faced by these people.